

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) What is the number of posts of the aforesaid cadre that are still vacant in the Ministry of Petroleum and Natural Gas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM FOTDUKHE): (a) and (b) The guidelines for the rotational policy for transfer of the officers of Indian Cost Accounts Service were approved in August, 1989. At that time two posts, one each of Deputy Director and Assistant Director in the Ministry of Petroleum & Natural Gas were included in the ICAS. Of these, the post of Deputy Director was lying vacant at the time of announcement of the guidelines and was filled in June, 1990 by promoting the Assistant Director already working in the Ministry of Petroleum & Natural Gas. Although he had completed more than 4 years in that Ministry, he was allowed to continue in view of the fact that he was due for superannuation in less than a year's time

(c) Two posts, one each of Deputy Director and Assistant Director, included in the ICAS, are lying vacant since 1-6-1991 and 28-6-1990 respectively.

**परीक्षाओं की जाली अंक-सूचियों की विलो**

1263. श्रीमती वीणा वर्मा :

श्री कपिल वर्मा :

कुमारी सईदा खातून :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कोशिश करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन समाचारों की ओर गया है जिनके अनुसार दिल्ली में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जाली अंक सूचियाँ बेची जा रही हैं, यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ

कालेजों में कुछ छात्रों को इन जाली अंक सूचियों के आधार पर प्रवेश दिया गया है; यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस घोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार क्या कड़े कदम उठाने का विचार कर रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हाँ। कुछ समाचार पत्रों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जाली अंक सूची से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। तथापि, सरकार को किसी विशेष मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) दिल्ली विश्व-विद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जाली अंक सूची के आधार पर किसी भी कालेज में किसी विशेष दाखिले के मामले की सूचना नहीं मिली है। जब भी फाइल का ऐसा कोई मामला सामने आयेगा, उसे कानून के अनुसार निबटारा ज़रूरी है।

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा प्रमाण-पत्र की अंक-सूचियों के संकलन में गलतियाँ

1264. श्री कपिल वर्मा :

कुमारी सईदा खातून :

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कोशिश करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की लापरवाही की वजह से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा प्रमाण-पत्र, 1991 की अंक-सूचियों में उत्तीर्ण शब्द की जगह कम्पाटिमेंट शब्द छप गया है, यदि हाँ, तो ऐसे कितने प्रमाण पत्र हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इस लापरवाही की वजह से कई छात्रों को कालेज में दाखिला नहीं मिल सकेगा, यदि हाँ, तो ऐसे छात्रों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन छात्रों को अब किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा है और दाखिला लेने की अंतिम तारीख भी निकल चुकी है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि कंप्यूटर की सहायता से हड़बड़ी में रिजल्ट तैयार करने के कारण कई तरह की गलतियाँ हुई हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली क्षेत्र में 41 परीक्षार्थियों की अंक सूचियों में 'उत्तीर्ण' शब्द के स्थान पर 'कम्पाटिमेंट' शब्द कंप्यूटर प्रोग्राम की त्रुटि के कारण भूल से छप गया है। आवश्यक संशोधनों के उपरान्त, के०मा० शि०बो० द्वारा ऐसे परीक्षार्थियों को संशोधित अंक सूचियाँ जारी कर दी गई हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली विश्व-विद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, यदि ऐसी शिकायतें नोटिस में लाई जाती हैं तो विश्वविद्यालय उन व्यक्तिगत शिकायतों की जांच-पड़ताल करेगा।

(घ) के. मा. शि. बो. के अनुसार 1991 में बोर्ड द्वारा संचालित 12वीं कक्षा की परीक्षा में उपस्थित हुए परीक्षार्थियों की अंक-सूचियों में कोई अन्य त्रुटि अभी तक बोर्ड के नोटिस में नहीं लाई गई है।

#### **Objectives of National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Financial Corporation**

1265. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) what is the object of National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Financial Corporation;

(b) what are the details of its programme and schemes to improve

the lots of Backward and Scheduled Castes people;

(c) what is the amount of assistance in terms of money (loan, aid), (separately) the corporation has given to the Scheduled Castes and Backward Classes;

(d) whether the Corporation has any objective schemes to assist entrepreneurs from Scheduled Castes and Backward Class to establish Small Scale Industrial Units; and

(e) if so, what is the number of entrepreneurs who have so far been given assistance and what is the amount spent on them (year wise figures from 1985-86 to 1991) with break up particulars for Scheduled Castes and Backward Class beneficiaries?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) The objective of the National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance and Development Corporation is to fill the critical gaps in the developmental programmes for Scheduled Castes and Scheduled Tribes by increasing the RLow of funds for income generating schemes by providing funds for economically viable and technically feasible projects.

(b) The Corporation is assisting programmes and schemes in the fields of agriculture, industry, transport and services sectors and training to inculcate/improve skills among Scheduled Castes and Scheduled Tribes to promote self-employment.

(c) A statement is laid on the table of the Sabha.

(d) Yes, Sir.

(e) A statement is laid on the Table of the Sabha.